बिहार राज्य

बनाम

एस के रॉय

25 अप्रैल 1966

[एम. हिदायतुल्ला और वी. रामास्वामी, न्यायमूर्तिगण]

कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजना अधिनियम, 1948, धारा 2(सी)-"नियोक्ता"-का अर्थ-"कोयला खदान" के "मालिक" के अर्थ के संदर्भ में-जैसा कि धारा 2 में परिभाषित किया गया है, खान अधिनियम, 1952।

प्रतिवादी के पास एक कोक प्लांट था जो मूल रूप से कोलियरी समूह का था लेकिन बाद में उसे हस्तांतरित कर दिया गया था। यह सतही भूमि पर एक कोयला खदान के निकट स्थित था जो कोयला क्षेत्रों का हिस्सा था जिसके नीचे कोयला खदान का काम किया जाता था। प्रतिवादी ने स्वयं कोयले का खनन या उत्खनन नहीं किया और न ही कोयला प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई संचालन किया। उनका कोक प्लांट एक उप-उत्पाद संयंत्र था जिसमें हार्ड कोक के साथ-साथ कुछ अन्य उप-उत्पादों का निर्माण किया जाता था।

प्रतिवादी पर कोयला खदान भविष्य निधि और बोनस योजना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 46) के तहत जारी कोयला खदान भविष्य निधि योजना के पैरा 70 के तहत, एक शिकायत पर मुकदमा चलाया गया था कि एक कोयला खदान के मालिक और एक नियोक्ता के रूप में- वह भविष्य निधि में कुछ योगदान का भुगतान करने में विफल रहा था। हालाँकि उन्हें ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया था और सत्र न्यायाधीश के समक्ष उनकी अपील खारिज कर दी गई थी, उच्च न्यायालय ने एक पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति दी और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

इस न्यायालय में अपील में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या प्रतिवादी खान अधिनियम, 1952 के धारा 2 के अर्थ के अंतर्गत कोयला खदान का मालिक था और इसलिए 1948 के अधिनियम 46 की धारा 2(ई) द्वारा परिभाषित एक नियोक्ता था। खान अधिनियम, 1952 की धारा 2(बी) में अभिव्यक्ति "कोयला खदान" का अर्थ है "कोई भी उत्खनन जहां कोई भी संचालन कोयला प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है और इसमें सभी कार्य, मशीनरी, ट्रामवे और साइडिंग शामिल हैं, चाहे वह जमीन के ऊपर या नीचे, कोयला खदान में या उसके निकट या उससे संबंधित हों।

आयोजित:

खान अधिनियम, 1952 की धारा 2(बी) के तहत प्रतिवादी कोयला खदान का मालिक नहीं था और उच्च न्यायालय ने उसे सही ही बरी कर दिया था। [264 सी]।

अभिव्यक्ति "कोयला खदान से संबंधित" धारा 2(बी) की परिभाषा के साथ कोयला खदान की गतिविधियों के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाली नियंत्रक अभिव्यक्ति है और सभी सहायक चीजें जैसे कार्य, मशीनरी, ट्रामवे और साइडिंग को "कोयला खदान" की

परिभाषा में तभी लाया जाता है जब वे कोयला खदान से संबंधित हों, यानी, यदि वे एक ही स्वामित्व में हों। विधायी इरादे को पूरा करने के लिए अधिनियम के धारा 2(बी) में "कोयला खदान" की परिभाषा में संयोजन "या" के स्थान पर संयोजन "और" को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है।[262 डी-ई)।

कोयला खदान भविष्य निधि और बोनस योजना (संशोधन) अधिनियम, 1965 की धारा 2(बी) और ऑरमंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम बेट्स: 1928 ए.सी. 143, 156; का संबोधन किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1965 की आपराधिक अपील संख्या 158।

1963 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1326 में बिहार उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15 सितंबर 1965 के खिलाफ अपील।

आर एच ढेबर, वी. डी. महाजुन और बी. आर. जी. के. अचार, अपीलकर्ता की ओर से।

एन. सी. चटर्जी, सुप्रकाश बनर्जी और सुकुमार घोष, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय रामास्वामी, जे. द्वारा सुनाया गया।

इस अपील में निर्धारण के लिए प्रस्तुत कानून का प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी - एस. के. रॉय- कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 46) के धारा 2(बी) और 2(ई), जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा, के अर्थ में 'कोयला खदान का मालिक' है।

कोयला खदान भविष्य निधि योजना (इसके बाद 'योजना' कहा जाएगा) के पैराग्राफ 70 के (ए), (डी) और (एफ) सपठित योजना के पैराग्राफ 33ए, 38, 42 और 69ए के उल्लंघन के लिए प्रतिवादी पर मुकदमा चलाया गया था। अधिनियम के तहत नियुक्त एक निरीक्षक ने प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया कि वह भौंरा कोक प्लांट का मालिक था और उसने योजना के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है। यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी अप्रैल, 1960 से नवंबर, 1960 तक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि के लिए योगदान का भुगतान करने में विफल रहा था और फॉर्म "ए" में संबंधित घोषणा के साथ फॉर्म "एच" में रिटर्न जमा करने में और विनियमों के तहत दिए गए फॉर्म 'पी' में विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा था। प्रतिवादी को मुकदमा चलाने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया और 500 रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई और, डिफ़ॉल्ट रूप से, अनुच्छेद 70 (ए) के तहत 3 महीने की साधारण कारावास से गुजरना होगा। प्रतिवादी ने सत्र न्यायाधीश के पास अपील की, जिन्होंने अपील खारिज कर दी और मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सजा की पुष्टि की। प्रतिवादी ने पटना उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जिसने पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि प्रतिवादी के स्वामित्व वाला कोक प्लांट योजना के अर्थ में कोयला खदान नहीं था और कोक संयंत्र योजना के प्रावधानों के अधीन नहीं था और प्रतिवादी अधिनियम और योजना के अर्थ के तहत खदान का मालिक नहीं था।

इस मामले में पाए गए या स्वीकार किए गए तथ्य हैं: (1) भौंरा कोक प्लांट मूल रूप से ईस्टर्न कोल कंपनी के स्वामित्व वाली भौंरा समूह की कोलियरियों का था, लेकिन बाद में 1945 से 1947 के वर्षों में कोक प्लांट को बिक्री द्वारा प्रतिवादी को स्थानांतरित कर दिया गया था, (2) भौरा कोलियरीज का समूह बाद में भौरा कांकानी कोलियरीज लिमिटेड को बेच दिया गया, (3) प्रतिवादी कोक प्लांट का मालिक और उस भूमि पर पट्टेदार है जिस जमीन के लिए जमीन के किराये के माध्यम से कुछ रॉयल्टी के भुगतान पर खड़ा है, पट्टादाता, प्रासंगिक समय पर, भौरा कांकानी कोलियरीज लिमिटेड कोयला खदान और कोयला क्षेत्र क्षेत्र का मालिक है, जहां भौरा कोयला खदानें हैं और कोक प्लांट स्थित है, (4) कोक प्लांट न केवल कोयला खदान के निकट है, बल्कि सतही भूमि पर भी स्थित है, जो कोयला क्षेत्रों का हिस्सा है और जिसके नीचे भौंरा कांकानी कोलियरीज लिमिटेडद्वारा कोयला खदान का काम किया जाता है। , (5) प्रतिवादी वहां किसी भी कोयला खदान का काम नहीं करता है। वह कोयला प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई भी कार्य करके कोयले का उत्खनन नहीं करता है, (6) कोक प्लांट एक उप-उत्पाद कोक संयंत्र है जिसमें हार्ड कोक के साथ-साथ कुछ अन्य उप-उत्पादों का निर्माण किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या तथ्यों की इस स्थिति में, प्रतिवादी अधिनियम और योजना के तहत कोयला खदान का मालिक है।

अधिनियम की धारा 2(ई) अभिव्यक्ति "नियोक्ता" का अर्थ है "कोयला खदान का मालिक" जैसा कि भारतीय खान अधिनियम, 1923 की धारा 3 के खंड (जी) में परिभाषित है। भारतीय खान अधिनियम, 1923 को निरस्त कर दिया गया है और खान अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम 35) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। बाद के अधिनियम में "मालिक" शब्द को सामान्य खंड अधिनियम के धारा 8 द्वारा धारा 2 के खंड 1 में परिभाषित किया गया है, अधिनियम के धारा 2 खंड e में "नियोक्ता" शब्द की परिभाषा को पुराने 1952 के अधिनियम 35 के धारा 2 खंड 1 में "मालिक" शब्द की परिभाषा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिसने पहले के अधिनियम को निरस्त कर दिया और इसे फिर से अधिनियमित किया (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम.पी. सिंह आदि में इस न्यायालय का निर्णय भी देखें ([1960]2SCR605)। धारा 2(1) के अनुसार 1952 के अधिनियम 35 के अनुसार "मालिक" शब्द का प्रयोग जब किसी खदान के संबंध में किया जाता है, तो इसका अर्थ है "कोई भी व्यक्ति जो खदान या उसके किसी हिस्से का तत्काल मालिक या पट्टेदार या अधिभोगी है और खदान के मामले में उसका व्यवसाय परिसमापक या रिसीवर द्वारा किया जा रहा है। ऐसे परिसमापक या प्राप्तकर्ता....."। अभिव्यक्ति "कोयला खदान" को अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में अलग से परिभाषित किया गया है, जिसे एफ के रूप में पढ़ा जाता है:

"2. (बी) 'कोयला खदान' का अर्थ है कोई भी उत्खनन जहां कोयला प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई भी कार्य किया गया है या किया जा रहा है, और इसमें सभी कार्य, मशीनरी, ट्रामवे और

साइडिंग, चाहे जमीन के ऊपर या नीचे, शामिल हैं या कोयला खदान के निकट या उससे संबंधित हो:

बशर्ते कि इसमें कोयला खदान का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं होगा जिस पर विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है जब तक कि ऐसी प्रक्रिया कोक बनाने या खनिजों की ड्रेसिंग की प्रक्रिया न हो;"

निर्माण के मामले में यह अवश्य माना जाना चाहिए कि सभी कार्य, मशीनरी, ट्रामवे और साइडिंग, चाहे जमीन के ऊपर या नीचे, कोयला खदान में या उसके निकट हों, इसके दायरे और परिभाषा के दायरे में केवल तब आएंगे जब वे कोयला खदान से संबंधित हों। दूसरे शब्दों में, मुख्य परिभाषा में "कोयला खदान से संबंधित" अभिव्यक्ति से पहले आने वाले "या" शब्द को "और" के अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए। कोई भी अन्य व्याख्या एक असामान्य और चौंकाने वाले परिणाम को जन्म देगी। कोई भी कार्य, मशीनरी, ट्रामवे और साइडिंग जो स्वामित्व के अर्थ में कोयला खदान से संबंधित नहीं हैं, अधिनियम के धारा 2 खंड b के पहले भाग में दी गई अभिव्यक्ति "कोयला खदान" के अर्थ में नहीं आ सकते हैं यदि वे कोयला प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्खनन कार्य करने के अर्थ में कोयला खदान से संबंधित हैं और उससे संबंधित हैं तो वे सहायक कार्यों, मशीनरी या इसी तरह के माध्यम से आएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए, कोयला क्षेत्र क्षेत्र में, सरकार से पट्टेदार एक खदान का काम कर रहा है, लेकिन ट्राम-वे और साइडिंग एक रेलवे कंपनी द्वारा केवल कोयले के परिवहन के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। यह कल्पना नहीं की जा सकती कि अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत ट्रामवे या रेलवे साइडिंग का मालिक कोयला खदान का मालिक है क्योंकि विधायिका का यह इरादा नहीं हो सकता था कि कोयले के परिवहन का कार्य, अपने आप में, अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत एक कोयला खदान के कामकाज का गठन करेगा। हमारी राय में, अभिव्यक्ति "कोयला खदान से संबंधित" धारा 2(बी) की परिभाषा के भीतर कोयला खदान की गतिविधियों के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाली नियंत्रक अभिव्यक्ति है और सभी सहायक चीजें जैसे कार्य, मशीनरी, ट्रामवे और साइडिंग को "कोयला खदान" की परिभाषा के भीतर तभी लाया जाता है जब वे कोयला खदान से संबंधित हों, यानी, यदि वे एक ही स्वामित्व में हों। इसलिए, हमारी राय है कि विधायी इरादे को पूरा करने के लिए अधिनियम के धारा 2(बी) में "कोयला खदान" की परिभाषा में संयोजन "और" के लिए संयोजन "या" को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है।

इस संबंध में, कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजना (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का अधिनियम 45) धारा 2(बी) में "कोयला खदान" शब्द की विस्तारित परिभाषा का उल्लेख करना वैध है जो इस प्रकार है:

"(2) खंड (बी) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(बी) 'कोयला खदान' का अर्थ है कोई भी उत्खनन जहां कोयले की खोज या प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई कार्य किया गया है या किया जा रहा है और इसमें शामिल हैं-

(i) सभी बोरिंग और बोर होल;

(ii) सभी शाफ्ट, कोयला खदान में या उसके निकट और कोयला खदान से संबंधित हैं, चाहे वे डूबने की प्रक्रिया में हों या नहीं;

(iii) संचालित होने के क्रम में सभी स्तर और झुके हुए विमान;

(v) कोयला या अन्य वस्तुओं को कोयला खदान में लाने या हटाने या वहां से कचरा हटाने के लिए प्रदान किए गए सभी कन्वेयर या हवाई रोप-वे;

(vi) कोयला खदान में या उसके निकट और उससे संबंधित सभी संपादन, स्तर, विमान, मशीनरी, कार्य, रेलवे, ट्रामवे और साइडिंग;

(vii) कोयला खदान के परिसर के भीतर और एक ही प्रबंधन के तहत स्थित सभी कार्यशालाएं और उस कोयला खदान या उसी प्रबंधन के तहत कई कोयला खदानों से जुड़े उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं;

.....

(ix) कोयला खदान या एक ही प्रबंधन के तहत कई कोयला खदानों में काम करने के उद्देश्य से बिजली की आपूर्ति करने वाले सभी बिजली स्टेशन;

(x) कोयला खदान से निकलने वाले कूड़े को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी परिसर, या जिसमें ऐसे कूड़े के संबंध में कोई संचालन किया जा रहा है, वह परिसर विशेष रूप से कोयला खदान के नियोक्ता के कब्जे में है;

.....

(xiii) किसी कोयला खदान में या उससे जुड़ा कोई परिसर, जिस पर कोयला खदान से जुड़ा कोई संयंत्र या अन्य मशीनरी स्थित है या जिस पर कोयला खदान के काम से संबंधित कोई प्रक्रिया चल रही है;"

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उप-खण्ड (vi) में यह प्रावधान किया गया है कि "कोयला खदान" शब्द में कोयला खदान में या उससे सटे सभी एडिट, स्तर, विमान, मशीनरी, कार्य, रेलवे, ट्रामवे और साइडिंग शामिल हैं। इसी प्रकार, खंड (vii) में इसमें "परिसर या कोयला खदान के भीतर और एक ही प्रबंधन के तहत स्थित सभी कार्यशालाएं शामिल हैं और उस कोयला खदान या एक ही प्रबंधन के तहत कई कोयला खदानों से जुड़े उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं"। पुनः, धार 2b खंड (ii) संशोधित धाराओं में कहा गया है कि "कोयला खदान" शब्द में "कोयला खदान में या उससे सटे और उससे संबंधित सभी शाफ्ट शामिल हैं, चाहे वे डूबने की प्रक्रिया में हों या नहीं"। इसी प्रकार, धारा 2b खंड (xiii) में प्रावधान है कि "कोयला खदान" शब्द में "कोयला खदान में या उससे जुड़ा कोई भी परिसर शामिल है, जिस पर कोयला खदान से जुड़ा कोई संयंत्र या अन्य मशीनरी स्थित है या जिस पर काम से संबंधित

कोई भी प्रक्रिया है एक कोयला खदान का काम चल रहा है"। हमारी राय में, संशोधित अधिनियम (1965 का अधिनियम 45) द्वारा लाए गए पहले अधिनियम के धारा 2(बी) की भाषा में परिवर्तन का उद्देश्य कानून में बदलाव लाना नहीं था बल्कि इस संबंध में कानून का उद्देश्य पिछले अधिनियम पर एक उचित व्याख्या तय करना था। निर्माण के मामलों से निपटने में यह एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि बाद के कानून को यह देखने के लिए देखा जा सकता है कि पहले के अधिनियम की उचित व्याख्या क्या है, जहां पहले का अधिनियम अस्पष्ट या संदिग्ध है या आसानी से इससे अधिक करने में सक्षम है। एक व्याख्या. (ऑरमंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम बेट्स([1928]AC143at P156) देखें।)

व्यक्त किए गए कारणों से, हम मानते हैं कि प्रतिवादी अधिनियम की धारा 2(बी) के अर्थ के भीतर कोयला खदान का मालिक नहीं है और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को योजना के तहत उसके खिलाफ लगाए गए अपराधों से बरी कर दिया है। हम तदनुसार इस अपील को खारिज करते हैं।

अपील खारिज।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar
Advocate Allahabad High Court